Tc.No. : GUJHIN00722

पेज: 4, मुल्य 1 रु.

क्रांति समय

संस्थापक / संपादक : सुरेश मौर्या

E-mail: krantisamay@gmail.com, www.krantisamay.com

वर्ष: 1 अंक: 02, 24 सितम्बर, रविवार 2017, सूरत, हिन्दी दैनिक 9879141480

4 ओ ब्लॉक आगम नवकार कॉम्पलेक्ष, सचीन रेल्वे स्टेशन के पास, सूरत-गुजरात

सार समाचार

यौन शोषण का आरोपी फलाहारी बाबा 15 दिन की न्यायिक हिरासत में

नई दिल्ली। यौन शोषण के आरोप में घिरे फलाहारी बाबा को आज राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फलाहारी बाबा पर छत्तीसगढ़ की एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। जिसके बाद अलवर पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार कर लिया। फलाहारी बाबा को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक बाबा के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि बाबा को प्राइवेट अस्पताल से निकाल कर अलवर के राजकीय अस्पताल में ले जाया गया है।

सीबीएसई के सर्करुलर के विरोध में 25 को बंद रहेंगे कई स्कूल

नई दिल्ली। सीबीएसई के एक सकरुलर और सरकार के आदेश के विरोध में दिल्ली के कई मान्यता प्राप्त निजी स्कूल सोमवार को बंद रहेंगे। इन स्कूलों का कहना है कि शिक्षा निदेशालय और बोर्ड के शिक्षकों के पुलिस सत्यापन और साइकोमीट्रिक टेस्ट कराने के आदेश से शिक्षकों का अपमान हुआ है। दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल्स मैनेजमेन्ट ऐसोसिएशन के सदस्य स्कूलों ने एक बैठक में यह फैसला लिया है। बैठक में कहा गया कि एक स्कूल की घटना के कारण सारे शिक्षा जगत को कटघरे में खड़ा करना, शिक्षकों को शक से देखना, अन्य कर्मचारियों को मुजरिम मानकर चरित्र प्रमाणपत्र मांगना, शिक्षक-शिक्षिकाएं दिमागी रूप से बीमार नहीं है इसका प्रमाणपत्र मांगना, शिक्षक-शिक्षिकाओं और स्कूल प्रबंधन का घोर अपमान है। एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी जैन ने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी कि शिक्षकों के इस अपमान को जनता के बीच में ले जाया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई मां-बाप अपने बच्चों को शिक्षक बनने के लिए प्रेरित न करे। जैन ने मांग है कि सीबीएसई अध्यक्ष और दिल्ली सरकार इन प्रकार के आदेश के लिए माफी मांगे।

रनहौला में पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। रनहौला क्षेत्र में युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। मृतक की शिनाख्त रॉकी के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार रॉकी की घटनास्थल पर मौजूद कुछ युवकों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद वहां मौजूद युवकों ने पत्थर से कुचलकर रॉकी की हत्या दी और मौके से फरार हो गए। रनहौला थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर छह आरापियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की शिनाख्त पंकज वर्मा (19), रोहित उर्फ पोली (25), रोहित उर्फ लाला (22), सोनू बंसल (20), दीपक उर्फ राजू (21) व धमेन्द्र (21) के रूप में हुई। रोहित उर्फ पोली उत्तमनगर और बाकी आरोपी महारानी एंक्लेव निवासी हैं। पुलिस के मुताबिक रॉकी परिवार के साथ हस्तसाल इलाके में रहता था और पिछले कुछ माह से नौकरी छोड़कर अपनी संपत्ति की देखभाल करता था। बृहस्पतिवार शाम विकासनगर क्षेत्र में एक प्लॉट में रॉकी व उसके जानकार दोस्त पार्टी करने आए थे। इस दौरान नशे में रॉकी की एक युवक से कहासुनी हो गई, जिसके बाद उसने रॉकी के सिर पर पत्थर से प्रहार कर दिया, जिससे रॉकी जमीन पर गिर पड़ा। वहां मौजूद युवकों ने रॉकी को पत्थर से कुचलने के बाद वहां से फरार हो गए। घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टर्माटम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है।

करोड़ों की ठगी का आरोपी तीन साल से था फरार

महिला मित्र के साथ भाग गया था शिमलारिश्तेदार से वसूली के लिए दिल्ली आने पर छापेमारी कर पुलिस ने पकड़ा

नई दिल्ली। पिछले तीन साल से बेइमानी व फाड्र के आरोपी तथा 20 हजार रपए के इनामी जालसाज विनय कुमार को बिंदापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विनय कुमार ने तिलकराज नामक एक व्यक्ति को बिंदापुर में फ्लैट दिलाने के नाम पर उससे 1.14 करोड़ की बेइमानी थी। इसस बाद तिलकराज ने 2014 में केस दर्ज कराया था। आरोपी के खिलाफ बिंदापुर थाने में सात और जगतपुरी थाने में एक अपराधिक प्रकरण दर्ज है।

घुसपैठ पर लगाम: उठाएगी ये सख्त कदम

रोहिंग्या को रोकने का नया प्लान तैयार

नई दिल्ली।

भारत ने रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सुरक्षा और कड़ी कर दी है। बीते दिनों खबर आई थी दो हजार रोहिंग्या भारत आ सकते हैं इसे लेकर केंद्र सरकार ने बाकी के राज्यों में अलर्ट कर दिया है। अब खबर है कि भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। अगर रोहिंग्या देश में घुसने की कोशश करते हैं तो बीएसएफजवान उन्हें रोकने के लिए चिली स्प्रे और स्टन ग्रेनेड (बेहोश करने वाले ग्रेनेड) का इस्तेमाल कर सकते हैं।

बॉर्डर पर जवानों को इस बात की परमिशन दे दी गई है कि रोहिंग्या मुसलमानों को देश में घुसने से रोकने के लिए जवान ये कठोर कदम उठा सकते हैं। बॉर्डर सिक्यॉरिटी फोर्स (बीएसएफ) के एक अधिकारी का कहना है कि हम उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना

कोर्ट सख्त: रोहिंग्या मुसलमानों पर स्ट्ट एक साल में करेगा फैसला

चाहते और न ही उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन हम रोहिंग्या को भारत में घुसने नहीं दे सकते।

पहचान ना जाहिर करने की शर्त पर अधिकारी ने बताया, जो रोहिंग्या भारत में घुसने की कोशिश करेंगे उन्हें रोकने के लिए हम स्टन ग्रेनेट और चिली स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे। अधिकारी का कहना था कि वो अपनी पहचान इसलिए नहीं जाहिर कर सकता क्योंकि उन्हें मीडिया से बात करने की परमिशन नहीं है।

बता दें कि भारत में करीब 40 हजार मुसलमान अवैध तरीके से रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों के भारत में रहने पर केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम

कोर्ट में 16 पन्नों का हलफनामा दायर कर कहा है कि रोहिंग्या मुसलमान भारत में अवैध तरीक से रह रहे हैं इसलिए उन्हें यहां रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। देश के सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि रोंहिग्या का पाकिस्तान और आतंकी संगठन इस्लामिल स्टेट से भी संपर्क हो सकता है जो कि देश के लिए खतरा है इसलिए उन्हें यहां रहने नहीं दिया जा सकता।

मनोज की सांसद निधि से 15 स्कूलों में सीसीटीवी शुरू

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 15 प्राथमिक स्कूल सीसीटीवी से दुरुस्त हो गये हैं। यह सीसीटीवी उत्तरी-पूर्वी दिल्ली के सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की सांसद निधि से लगाये गये हैं। इसके लिए उन्होंने करीब दो करोड़ रपए आवंटित किये थे। उन्होंने अपने सभी सहयोगी सांसदों से आग्रह किया है कि वह अपने-अपने इलाके के स्कूलों में सीसीटीवी लगाने की पहल करें। जिससे स्कूलों में होने वाली दुर्घटनाओं और बच्चों की पढ़ाई पर नजर रखी जा सके। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि स्कूलों का मामला बेहद संवेदनशील है और इसे दिल्ली सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी सांसद निधि से स्कूलों में सीसीवीटी लगाने का निर्णय लिया था। उनका कहना है कि केजरीवाल ने चुनाव से पहले 15 लाख सीसीटीवी लगाने का दावा किया था, लेकिन अब तक इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है।

बेनामी संपत्ति का पता बताओ, 1 करोड़ का इनाम पाओ

नई दिल्ली। केंद्र सरकार कालेधन के खिलाफ मुहिम को और धार देने जा रही है। सूत्रों की मानें तो सरकार बेनामी संपत्ति रखने वालों की उपयोगी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को देने वालों को एक करोड़ रुपये इनाम देने की योजना बना रही है। इसकी घोषणा अगले महीने हो सकती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि योजना के तहत बेनामी संपत्ति को जानकारी देने वालों को योजना के तहत 15 लाख रुपये की इनाम दी जाएगी। यह राशि सूचना की सटीकता और बेनामी संपत्ति की कीमत के आधार पर एक करोड़ रुपये तक हो सकती है। अधिकारी ने बताया कि इनाम के लिए बेनामी संपत्ति की जानकारी सटीक और पुख्ता होनी चाहिए। वहीं,सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। विभाग सूचना देने वाली की पहचान कभी जाहिर नहीं करेगा, क्योंकि इससे उनके जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा, बेनामी संपत्ति का पता लगाना चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसमें अगर लोगों की मदद मिले तो यह बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आसपास के लोगों को पता होता है कि कौन बेनामी संपत्ति बना रहा है। उन्होंने कहा, फिलहाल यह प्रस्ताव वित्तमंत्रालय की मंजूरी के लिए विचाराधीन है। एक बार इसकी हरी झंडी मिलने पर सीबीडीटी औपचारिक रूप से अगले महीने ऐलान करेगा।

अधिकारी ने बताया कि इनाम के लिए बेनामी संपत्ति की जानकारी सटीक और पुख्ता होनी चाहिए। वहीं,सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।

पहले भी मिलते थे पुरस्कार

खबरी को पुरस्कृत करने की व्यवस्था पहले से है। प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग , राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई)अकसर खबर देने वालों को पुरस्कार राशि देते हैं। लेकिन एकमुश्त इतनी बड़ी राशि देने का प्रावधान अबतक नहीं था। इसलिए लोग कम आकर्षित होते थे।

पिछले साल अमल में आया नया कानून

संसद ने बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन कानून 2016 पिछले साल पारित किया था। जबकि 1 नवंबर 2016 से यह कानून प्रभावी हुआ है। सरकार ने अगस्त तक इस कानून के तहत 800 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।

क्या है बेनामी संपत्ति

बेनामी संपत्ति की अभिप्राय ऐसी संपत्ति से है जो व्यक्ति अपनी काली कमाई से दूसरे के नाम पर खरीदता है। इस प्रकार दस्तावेजों में वह संपत्ति किसी और के नाम होती है। लेकिन वास्तविक मालिक कोई और होता है।

लालू प्रसाद परिवार भी शिकंजे में

आयकर विभाग ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी, बेटी मीसा भारती पर बेनामी संपत्ति की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही करीब 165 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।

उमस से मिली लोगों को राहत

बारिश से गिरा पारा, सड़कों पर लगा जाम

मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटे तक इसी तरह से बारिश होने की संभावना जतायी है।

नई दिल्ली।

लौटते मानसून ने शुक्रवार को दिल्ली को पानी-पानी कर दिया। दिनभर हुई बारिश से जहां एक ओर तापमान में भारी गिरावट आई वहीं दूसरी ओर दिनभर सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। बारिश के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में महज एक डिग्री सेल्सियस का अंतर रहा। शुक्रवार सुबह से ही दिल्ली के आसमान में बादलों की आवाजाही जारी थी। ग्यारह बजे के आसपास बादलों ने बरसना शुरू कर दिया, जो दिनभर जारी रहा। मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटे तक इसी तरह से बारिश होने की संभावना जतायी है। इस बीच कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है।

दिनभर में दिल्ली में औसत बारिश का आंकड़ा 18.4 एमएम दर्ज किया गया, जबकि अब तक पूरे सीजन में दिल्ली में 21 सितम्बर तक 616.6 एमएम बारिश हो चुकी है। इस हिसाब से दिल्ली में अब तक जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी हो चुकी है। इस सीजन के समाप्त होने में अभी एक सप्ताह का समय और है। बारिश से अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरकर 27.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया जबकि

शुक्रवार का न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक रहा।

इस हिसाब से देखा जाए तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान में महज एक डिग्री सेल्सियस का अंतर रहा। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कल भी बारिश होने और तापमान के 30 और 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। बारिश से जगह-जगह सड़कों पर पानी भर गया, जिससे कई जगह जाम लग गया। दोपहर में स्कूल से घर जाने वाले छात्र और शाम को दफ्तर से घर लौटने वाले भी जाम में फंसे। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार बारिश के कारण पारस फ्लाई ओवर,मोदी मिल्स फ्लाई ओवर और आईटीआई फ्लाई ओवर पर जाम लग गया जिससे स्कूल से वापस आने और कार्यालय से वापस लौटने वालों को काफी मुश्किलें हो रही हैं।

बारिश से बचने को बाइक सवारों ने पुलों के नीचे और कई लोगों ने मेट्रो स्टेशनों के नीचे शरण ली। बारिश का असर लक्ष्मी नगर, विकास मार्ग, आनंद विहार, आईटीओ, कनाट प्लेस, करोल बाग, अजमेरी गेट, लाल किला, बस अड्डा, आजादपुर, भजनपुरा, यमुना विहार, नंद नगरी, दुर्गा पुरी, सीलमपुर, शहादरा आदि इलाको में लोग घंटो जाम में फंसे रहे।

इंसाफ की आस:

प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में सीबीआई ने दर्ज किया केस, जांच शुरू

नई दिल्ली।

सीबीआई शुक्रवार को दिल्ली से सटे गुरुग्राम स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न की हत्या की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की अनुशंसा पर मामले में सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी की थी। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार से अधिसूचना प्राप्त होने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली है। एजेंसी ने गुरुग्राम के भोंडसी पुलिस थाने में 8 सितंबर को दर्ज एफआईआर संख्या 250 के मामले को औपचारिक रूप से अपने हाथ में ले लिया है। यह एफआईआर हत्या, आर्म्स एक्ट, पोक्सो कानून धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई अब तक की जांच मामले में एकत्र किए गए सबूतों को अपने कब्जे में लेगी। साथ ही उस स्थान का नए सिरे से फॉरेंसिक टीम से जांच कराई जाएगी।

मां कसम हिन्दुस्तान स्वच्छ रखेंगे हम'

दिल्ली। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह दो घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा और न किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मुहल्ले से, मेरे गांव से और मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण है कि वहां के नागरिक न गंदगी करते और न ही होने देते हैं।इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं, वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा।

34 वर्षीय सुशील इससे पहले वर्ष 2011 में अचानक देशभर में चर्चित हो गए थे

विजेता सुशील कुमार हुए पास, बनेंगे टीचर

पटना।

कौन बनेगा करोड़पति के विजेता रहे सुशील कुमार एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अब वे टीईटी में सफल होने के चलते खबरों में हैं। टीईटी में सफलता पाने के बाद उन्हें बिहार सरकार के स्कूल में बतौर शिक्षक काम करने और बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा।

बिहार के मोतिहारी निवासी 34 वर्षीय सुशील इससे पहले वर्ष 2011 में अचानक देशभर में चर्चित हो गए थे। वे न केवल केबीसी में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे बल्कि सभी सवालों का जवाब देकर पांच करोड़ का इनाम भी जीते थे।

रातों-रात बन गए थे सेलिब्रेटी

इस सफलता के बाद सुशील बिहार सहित पूरे देश में सुर्खियों में आ गए थे। लोग उनके पीछे ऑटोग्राफ लेने और सेल्फी के लिए भागने लगे थे। इसके बाद तो वे सेलिब्रेटी बन गए हैं। सुशील ने शुक्रवार को हिन्दुस्तान के साथ बातचीत में अपनी इस सफलता को साझा किया। उन्होंने अपने सोशल साइट्स वॉल पर गुरुवार की रात इसकी चर्चा की थी।

परीक्षा में 34741 छात्र असफल

बिहार टेट में 1 से 5 की परीक्षा में 49488 निबंधन किया गया है। इस परीक्षा में 7338 छात्र पास हुए है। वहीं 34741 छात्र असफल रहे। वहीं 6 से 8 की परीक्षा में 1 लाख 64 हजार छात्रों ने भाग लिया था। जिसमें 20, 113 छात्र पास हुए और 2234 छात्र असफल रहे।

बिहार टीईटी में 12त्न महिलाएं पास

एक से 5वीं में 17 हजार 379 और छठी से 8वीं में 76 हजार 373 महिलाएं परीक्षा में शामिल हुई थीं। इस तरह देखा जाए तो दोनों परीक्षा में 93 हजार 752 महिला अभ्यर्थी शामिल हुईं। इसमें से 11 हजार 186 पास हुईं। यानी इनके पास होने का प्रतिशत 11.92 फीसदी रहा।

बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर परीक्षा के बाद अब बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का रिजल्ट भी कम रहा

है। परीक्षा में 17.47 फीसदी अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। पहली से 5वीं कक्षा में 16.07 फीसदी और छठी से 8वीं में 17.84 फीसदी ही सफल रहे।

क्रांति बैठे-ठालों का खेल नहीं है।
वह नई सभ्यता को जन्म देती है -प्रेमचंद

मूर्ति विसर्जन को लेकर टिप्पणिया

कोलकाता उच्च न्यायालय ने दुर्गा मूर्ति विसर्जन को लेकर जो कुछ टिप्पणियां की हैं वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए तीखी निंदा ही है। अगर न्यायालय कह रहा है कि दोनों समुदाय के बीच सद्भाव बने रहने दीजिए तो इसका अर्थ यही निकलता है कि ममता के आदेश को न्यायालय सद्भाव तोड़ने वाला मानता था। वास्तव में ममता ने जिस तरह यह आदेश जारी कर दिया कि मोहर्रम को देखते हुए 30 सितम्बर की शाम 6 बजे से लेकर 2 अक्टूबर की सुबह तक दुर्गा मूर्ति का विसर्जन नहीं किया जाएगा, उससे हिन्दुओं के अंदर गुस्सा का भाव पैदा हुआ था। इसे एक समुदाय के तुष्टिकरण के रूप में देखा जाना भी स्वाभाविक था। आखिर दो समुदाय अपने-अपने पर्व एक साथ क्यों नहीं मना सकते। यदि सुरक्षा की समस्या है तो यह सरकार की जिम्मेवारी थी। किंतु अपनी जिम्मेवारी पूरी करने की जगह आप पर्व को ही रोक दीजिए तो फिर न्यायालय या कहीं उसका समर्थन नहीं मिल सकता। न्यायालय ने कहा भी कि रेगुलेशन यानी नियमन एवं प्रोहिबिशन यानी बंदिश में अंतर होता है। ममता ने पहले की जगह दूसरे विकल्प को अपनाया, जिसका कोई कानूनी आधार नहीं था। यह एक समुदाय के धार्मिक अधिकारों पर चोट भी था। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार मूर्तियों के विसर्जन और मोहर्रम के जुलूस के लिए अलग-अलग रूट तय करे और पुलिस यथोचित सुरक्षा की व्यवस्था करे। यही व्यावहारिक एवं उपयुक्त है। किंतु ममता बनर्जी न्यायालय के निर्णय को सकारात्मक भाव से लेने की जगह साफ नाखुशी जाहिर कर रहीं हैं। वह कह रहीं हैं कि कोई उनकी गर्दन काट ले लेकिन उन्हें अपना सिद्धांत बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इसका अर्थ क्या है? उन्होंने न्यायालय की आलोचना नहीं की लेकिन अपने निर्णय को अब भी सही ठहरा रहीं है। विसर्जन के लिए पुलिस की अनुमति लेनी होगी। तो क्या अब लोग पुलिस से विसर्जन की अनुमति लेने जाएंगे और पुलिस कहेगी तो करेंगे? क्या पुलिस के लिए उच्च न्यायालय का आदेश नहीं है? अदालत के आदेश के बाद पुलिस की भूमिका यह तय करने की नहीं रह गई है कि मूर्ति विसर्जन अपनी निर्धारित तिथि को हो या नहीं। उसकी भूमिका केवल विसर्जन बिना किसी हिंसा और बाधा के संपन्न हो जाए ऐसी व्यवस्था करने तक सीमित रह गई है। ममता को इसे समझना चाहिए। यह भी समझना होगा कि जज भी इसी समाज के हैं और उन्हें भी अमन की चिंता होगी।

''कोल्ड स्टार्ट डाक्ट्रीन'

आतंकवाद को लेकर विशेषकर कश्मीर में पाकिस्तान परस्त आतंकवादी संगठनों पर भारत की आक्रामक नीति के बाद से पाकिस्तान को कुछ भी नहीं सूझ रहा है। थक-हारकर उसने उत्तर कोरिया वाली शैली में अब भारत को आंखें दिखाने की भौंडी कोशिश यह कहकर की है कि उसने भारत की ''कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रीन' से निपटने के लिए कम दूरी के एटमी हथियार विकसित किए हैं और इसका और कोई अर्थ नहीं निकाला जाए। हालांकि पाकिस्तान की इस गीदड़ भभकी का भारत के लिए कोई मतलब नहीं है, फिर भी यह देखना दिलचस्प है कि पाकिस्तान की यह स्वीकारोक्ति उस देश में हुई है, जो इस वक्त आतंकवाद खासकर पाकिस्तान में आतंकवादियों की हमदर्दी और शरणस्थली को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित और आक्रामक है। एक वक्त ऐसा भी था, जब भारत की हर दलील और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को बेपर्दा करने का हर सबूत अमेरिका को झूठा लगता था। लेकिन अब हर चीज साफ है। पाकिस्तान को यह भी पता चल चुका है कि अमेरिका के नये राष्ट्रपति ट्रंप उसके बारे में कैसे विचार रखते हैं? शायद अमेरिका के दिल में एक बार फिर जगह बनाने और लगे हाथ भारत को परमाणु हथियार का भय दिखाकर पाकिस्तान इसी संतुलन को साधने की कोशिश में है। लेकिन कहते हैं न कि जरूरत से ज्यादा चालाक बनना नुकसानदेह होता है। यही बात पाकिस्तान के संदर्भ में सटीक बैठती है। भारत की डॉक्ट्रीन की आड़ लेकर भले उसने अपने पास परमाणु हथियार होने की बात स्वीकार कर ली, लेकिन वह इस आरोप को कैसे झुठला सकता है कि वह तेजी से परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। और यह आरोप उसी शीर्ष अमेरिकी थिंक टैंक का है। वह इस आरोप से भी कैसे पीछा छुड़ा सकता है कि आज अमेरिका जैसी महाशक्ति पर हाइड्रोजन और आणविक बम गिराने की धमकी देने वाला पिद्दी सा देश उ. कोरिया को यह ताकत उसी पाकिस्तान ने दी है। पाकिस्तान ने अपनी सफाई में यह कहा कि उसका परमाणु हथियारों का जखीरा पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन आतंकवादियों का पनाहगाह बन चुके देश में ''सुरक्षित' होने का दावा बिल्कुल झूठा और हास्यास्पद है। और इसे विश्व का हर मुल्क भली-भांति समझता है। फिर भी भारत को अपनी तैयारियों को लेकर बेहद सतर्क और चुस्त-दुरुस्त रहने की दरकार है। साथ ही आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर नियंतण्र स्तर पर वैंकि कसने की जरूरत है।

सत्संग

अनुभव

कहा गया है कि बड़े तनावपूर्ण समय में-सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक उथल-पुथल के समय में-विराट शुभ संभव होता है। क्या यह सूत्र इसी घटना की तरफ इंगित करता है जिसका कि हमें यहां पूना में आपके सान्निध्य में अनुभव मिल रहा है? हां, संकट की घड़ी बहुत कीमती घड़ी है। जब सब चीजें व्यवस्थित होती हैं, कहीं कोई संकट नहीं होता तो चीजें मर जाती हैं। जब कुछ बदल नहीं रहा होता और पुराने की पकड़ मजबूत होती है, तो करीब-करीब असंभव ही होता है स्वयं को बदलना। जब हर चीज अस्त-व्यस्त होती है, कोई चीज स्थायी नहीं होती, सुरक्षित नहीं होती, कोई नहीं जानता कि अगले पल क्या होगा-ऐसे अराजक समय में तुम स्वतंत्र होते हो, रूपांतरित हो सकते हो, उपलब्ध हो सकते हो अपनी अंतस सत्ता के आत्यंतिक केंद्र को। यह जेल जैसा ही है: जब हर चीज सुव्यवस्थित होती है तो किसी कैदी के लिए उससे बाहर आना, जेल से भाग निकलना करीब-करीब असंभव ही होता है। लेकिन जरा सोचो : भूचाल आया हो और हर चीज अव्यवस्थित हो गई हो और किसी को पता न हो कि पहरेदार कहां हैं, जेलर कहां है और सारे नियम टूट गए हों और हर कोई अपनी जान बचा कर भाग रहा हो-तो उस क्षण में अगर कैदी जरा भी सजग हो तो वह बड़ी आसानी से भाग सकता है; यदि वह बिल्कुल मूर्ख है, केवल तभी वह इस अवसर को चूकेगा। जब समाज उथल-पुथल में होता है, और हर चीज संकट में होती है, तो एक अराजकता फैल जाती है। इस समय यदि तुम चाहो, तो निकल सकते हो कैद से। यह बहुत आसान है, क्योंकि कोई तुम्हारे पीछे नहीं है। तुम अकेले हो। परिस्थिति ऐसी है कि हर कोई अपनी फिक्र कर रहा होता है-तुम्हारी तरफ कोई नहीं देख रहा होता। यही है घड़ी। चूकना मत इस घड़ी को। बहुत संकट की घड़ियों में लगभग सदा ही बहुत लोगों को बुद्धत्व घटा है। जब समाज बहुत व्यवस्थित होता है, और करीब-करीब असंभव ही होता है विद्रोह करना, अतिक्रमण करना, नियमों का अनुसरण न करना तो बुद्धत्व ज्यादा कठिन हो जाता है-क्योंकि बुद्धत्व है स्वतंत्रता; बुद्धत्व है परम स्वच्छंदता। वस्तुतः वह है समाज से हटना और एक व्यक्ति बनना। समाज पसंद नहीं करता व्यक्तियों को : वह पसंद करता है यंत्र-मानवों को जो लगते तो हैं बिल्कुल व्यक्तियों की भांति, लेकिन व्यक्ति होते नहीं। समाज प्रामाणिक व्यक्ति को पसंद नहीं करता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक

निस्संदेह इस समय देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाना जरूरी है। हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) में विकास दर घटकर 5.7 फीसद रह गई,जो पिछली तिमाही के 6.1 फीसदी से भी कम है। ऐसे में अर्थव्यवस्था की गति धीमी होने और विकास दर घटने के ऐसे परिदृश्यय को बदलने और विकास को गति देने के लिए भारत को सतत सुधार की जरूरत है। नया आर्थिक माहौल और नई आर्थिक रणनीति विकसित करना आवश्यक है। लेकिन सरकार को बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और सेवा क्षेत्र के योगदान के मौजूदा स्तर को बढ़ाना होगा।

सतीश पेडणोकर

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को गति देने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में विकास के साथ-साथ रोजगार बढ़ाने से संबंधित कदम उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि 19 सितम्बर को स्टेट बैंक ऑफइंडिया (एसबीआई) रिसर्च ग्रुप द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सितम्बर, 2016 से धीमी गति से आगे बढ़ रही है। अब यदि अर्थव्यवस्था में गतिशीलता नहीं बढ़ाई गई तो अर्थव्यवस्था में सुस्ती की आशंका बढ़ेगी। इससे निपटने के लिए अब सार्वजनिक खर्च बढ़ाना जरूरी हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार को सार्वजनिक व्यय बढ़ाने के लिए राजकोषीय घाटा बढ़ाने का भी कदम उठाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि सार्वजनिक व्यय बढ़ने के कारण नियंतण्र क्रेडिट रेटिंग घटने की चिंता नहीं की जानी चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम की उस उपधारा का इस्तेमाल कर सकती है, जिसके तहत राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में 0.5 फीसद गिरावट की अनुमति है। इस रिपोर्ट ने सरकार को छोटी अवधि की अतिरिक्त उधारी की गुंजाइश भी टटोलने की सलाह दी है। इस बारे में कहा गया है कि छोटी अवधि की उधारी बढ़ाई जा सकती है। निस्संदेह इस समय देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाना जरूरी है।

हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) में विकास दर घटकर 5.7 फीसद रह गई,जो पिछली तिमाही के 6.1 फीसदी से भी कम है। ऐसे में अर्थव्यवस्था की गति धीमी होने और विकास दर घटने के ऐसे परिदृश्यय को बदलने और विकास को गति देने के लिए भारत को सतत सुधार की जरूरत है। नया आर्थिक माहौल और नई आर्थिक रणनीति विकसित करना आवश्यक है। लेकिन सरकार को बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और सेवा क्षेत्र के योगदान के मौजूदा स्तर को बढ़ाना होगा। अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर पैदा करना होंगे। यह भी जरूरी है कि नोटबंदी और जीएसटी लागू होने से पैदा हुई शुरुआती परेशानियों और उसके कारण सुस्त हुई अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से अब अर्थव्यवस्था को ऊंचाई देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अहम भूमिका बनाई जानी होगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ''मेक इन इंडिया' योजना को गतिशील करना होगा। उन ढांचागत सुधारों पर भी जोर दिया जाना होगा, जिससे निर्यातोन्मुखी विनिर्माण क्षेत्र को गति मिल सके। ऐसा किए जाने से भारत में आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की नई संभावनाएं आकार ग्रहण कर सकती हैं। पिछले दिनों प्रकाशित विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देकर भारत चीन और पश्चिमी देशों को पीछे छोड़कर दुनिया का नया कारखाना बन सकता है। यद्यपि इस समय दुनिया के कुल उत्पादन का 18.6 फीसद उत्पादन अकेला चीन करता है। लेकिन कुछ वर्षो से चीन में आई लगातार सुस्ती एवं युवा कार्यशील आबादी में कमी और बढ़ती श्रम लागत के कारण चीन में औद्योगिक उत्पादन में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में उत्पादन गुणवत्ता के मामले में चीन से आगे चल रहे भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ने की अच्छी संभावनाएं मानी जा रही हैं। ख्यात नियंतण्र शोध संगठन स्टैटिस्टा और डालिया रिसर्च द्वारा मेड इन कंट्री इंडेक्स 2016 में उत्पादों की साख के अध्ययन के आधार पर कहा गया है कि गुणवत्ता के मामले में मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना से आगे है। इस सव्रेक्षण के तहत लिये गए मानकों में उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा मानक,

कीमत वसूली, विशिष्टता, डिजाइन, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, भरोसा, टिकाऊपन, सही उत्पादन और प्रतिष्ठा शामिल हैं। यूरोपीय संघ और दुनिया के 49 बड़े देशों को लेकर जारी इस इंडेक्स में उत्पादों की साख के मामले में चीन भारत से सात पायदान पीछे है। देश में प्रभावी मांग बढ़ाने और तेज विकास दर के लिए ऐसे प्रयास किए जाने होंगे, जिससे आम आदमी की मुट्ठी में कुछ अधिक धन आए और उसकी क्रयशक्ति क्षमता बढ़े। प्रभावी तरीके से महंगाई रोकना होगी।

महंगाई बढ़ाने वाले मध्यस्थों का दुष्चक्र रोकना होगा। एक ओर हमें शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े युवाओं को कौशल विकास से लबरेज करना होगा। रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों से शिक्षित करना होगा, वहीं गांवों में जो गरीब, अशिक्षित और अर्धशिक्षित लोग हैं, उन्हें अर्थपूर्ण रोजगार देने के लिए निम्न तकनीक विनिर्माण जुटाना होगा। इनके साथ-साथ श्रम सुधार, बैंकिंग सुधार, वित्तीय सुधार की डगर पर भी आगे बढ़ना होगा। नई पीढ़ी को हमें नए आर्थिक माहौल के अनुरूप पल्लवित-पुष्पित करना होगा। आर्थिक स्थायित्व और विकास दर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षो में जो विभिन्न ऐतिहासिक नीतिगत फैसले लिये गए हैं, उन्हें जल्द-से-जल्द कार्यान्वित किया जाना होगा। साथ ही, संसद में पारित कराए गए अभूतपूर्व आर्थिक सुधारों को कारगर तरीके से लागू किया जाना होगा। इन सबके साथ-साथ यह भी जरूरी है कि वित्त मंत्रालय सरकार की आय और खर्च का खाका तैयार करने के साथ सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) की वृद्धि दर में गिरावट पर लगाम लगाने के उपायों के बारे में प्रमुख मंत्रालयों के साथ त्वरित रूप से विचार मंथन करे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय पिछली परियोजनाओं को गतिशील करने और नई परियोजनाओं को शीघ्र लागू करने की दिशा में आगे बढ़े। अब अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए विकास के लक्ष्यों के लिए नीति आयोग द्वारा पिछले माह 29 अगस्त को प्रस्तुत सुधारवादी एजेंडे पर ध्यान दिया जाना होगा। इस एजेंडे में विनिर्माण, छोटे एवं मझौले उद्योग, निर्यात, कृषि और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीतियों की अहम भूमिका की बात कही गई है। हम आशा करें कि नरेन्द्र मोदी सरकार नीति आयोग के सुधारवादी एजेंडे को कार्यान्वित करने के लिए कारगर प्रयास करेगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी जा सकेगी।

चलते चलते

रोहिंग्या शरणाथी

बेचारे राजनाथ बाबू ने यह क्या कह दिया कि रोहिंग्या शरणार्थी नहीं हैं, भाई लोग उसी को ले उड़े। व्यंग्य वाणों की बारिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार वालों की बाकी हर चीज की तरह, उनकी हिंदी भी अनोखी है। उसमें शरणार्थी जैसे शब्दों के भी अलग ही अर्थ होते हैं। जब नोटबंदी पब्लिक पर भारी पड़ती है, तो सरकार की भाषा में वह गरीबों के भले की चीज होती है।

अब सैकुलर ब्रिगेड बेचारे राजनाथ सिंह के पीछे पड़ गई। बेचारे राजनाथ बाबू ने यह क्या कह दिया कि रोहिंग्या शरणार्थी नहीं हैं, भाई लोग उसी को ले उड़े। व्यंग्य वाणों की बारिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार वालों की बाकी हर चीज की तरह, उनकी हिंदी भी अनोखी है। उसमें शरणार्थी जैसे शब्दों के भी अलग ही अर्थ होते हैं। जब नोटबंदी पब्लिक पर भारी पड़ती है, तो सरकार की भाषा में वह गरीबों के भले की चीज होती है। जब जीएसटी से सब व्यापार-कारोबार चौपट हो जाते हैं, उनकी भाषा में यह राष्ट्रहित में जरूरी होती है। पब्लिक को परेशान करने वाली ऐसी हरेक चीज, सरकार के ''हिम्मतवर' होने का, उसकी छप्पन इंच की छाती का सबूत होती है, सो ऊपर से। जब जीडीपी बैठ जाती है, तो यह दो दिन की परेशानी और हमेशा की आसानी होती है। और जब रोजगार मिलने के बजाए छिनने लगते हैं, तो यह भारत की तरक्की से जलने वालों का दुष्प्रचार होता है। क्या अचरज कि उनकी हिंदी में शरणार्थी का मतलब शरण चाहने वाले की जगह कुछ और होता है। रोहिंग्या जान बचाकर भाग कर शरण की उम्मीद में आए हैं, वह तो उनके माथे पर लिखा है। आम पब्लिक की हिंदी के लिए, शरणार्थी होने के लिए इतना काफी है। पर मोदी सरकार की हिंदी के लिए नहीं। उसकी हिंदी में ऐसे शरण मांगने वालों के लिए एक अजब-सा शब्द है- अवैध अप्रवासी। भला ये अवैध अप्रवासी क्या बला है? शुक्र है कि भाषा में अब इन सेकुलरवालों की नहीं चल रही है। इनका बस चलता तो बेचारी हिंदी अवैध अप्रवासियों को पहचान ही नहीं पाती।

आखिर, पहचानती तो तब जब जानती कि अवैध अप्रवासी क्या है? हिंदी को राजनाथ बाबू का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने अवैध अप्रवासी की पहचान कराई। बताया कि वो दिन लद गए जब हरेक शरण चाहने वाला शरणार्थी मान लिया जाता था। अब नहीं। देशभक्तों के राज में और नहीं। अब तो वही शरणार्थी माना जाएगा, जो मंदिर में घंटा बजाएगा। ऐसा नहीं कर पाएगा तो मांगता रहे शरण, शरणार्थी नहीं माना जाएगा। हां! आतंकवादी जरूर माना जा सकता है, ताकि जबरन वापस भेजते हुए दिल में दर्द न हो।

मुद्दा

"नॉन-परफॉर्मिंग"

राजस्थान की सरकार ने विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) का रास्ता चुना है। उसका मानना है कि इस मॉडल द्वारा ''नॉन-परफॉर्मिंग'' विद्यालयों में पढ़ने-पढ़ाने की संस्कृति में सुधार किया जा सकता है। नॉन-परफॉर्मिंग विद्यालय से सरकार का क्या मतलब? इसे ख़बर के तीन वाक्यांशों से समझा जा सकता है। पहला, जिनके परीक्षा परिणाम खराब हैं। दूसरा, इनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में हैं। तीसरा, ये सभी विद्यालय सरकार द्वारा संचालित हैं। इस तरह से यह योजना निजी विद्यालयों की गुणवत्ता को पूरी तरह से क्लीन चिट देती है। समस्याग्रस्त विद्यालयों की अवस्थिति को दूरदराज के क्षेत्रों में स्वीकारती है, जहां सरकारी विद्यालय ही समाज के वंचित वर्ग के लिए औपचारिक शिक्षा का एकमात्र माध्यम हैं। सवाल है कि शिक्षा जैसी अति आवश्यक लोकवस्तु के संदर्भ में यह मॉडल कितना कारगर होगा? प्रस्तुत पीपीपी मसौदे के अनुसार निजी क्षेत्र से जो भागीदार सरकारी विद्यालयों के उद्धार का जिम्मा उठाना चाहते हैं, वे सरकार को 75 लाख रुपये प्रति विद्यालय का भुगतान करेंगे। सरकार 16 लाख रुपये सालाना की दर से 7 वर्ष में इसकी प्रतिपूर्ति करेगी। इस धन का प्रयोग आधारभूत संसाधनों के विकास हेतु किया जाएगा। इस गुलाबी तर्क के बरक्स पहला सवाल है कि एक विद्यालय के संचालन के लिए इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान कौन करेगा? अधिकांश गैर लाभकारी संगठन किसी औद्योगिक घराने की तरह न तो आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ हैं न ही बैंक या किसी अन्य माध्यम से उधार लेकर इतना बड़ा जोखिम उठाना चाहेंगे। स्वाभाविक है कि जो निजी निवेशक इस निवेश के लिए आकर्षित होंगे वे बड़े औद्योगिक घराने होंगे। किसी बड़े लाभ के अभाव में वे इतना बड़ा निवेश क्यों करेंगे? विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों पर किसका मालिकाना हक है? कौन वित्त दे रहा है? कौन प्रबंध कर रहा है? जैसे सवालों के उत्तर सरकार खोज रही है जबकि किसे, क्या, कौन और कैसे पढ़ा रहा है? जैसे औचित्यपूर्ण सवाल नहीं पूछे जा रहे। वास्तव में ये प्रक्रियागत सवाल ही शिक्षा की गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। सरकार ''बच्चे पढ़ते नहीं', ''शिक्षक आते नहीं', ''आते हैं तो पढ़ाते नहीं' जैसे आधारहीन तकरे के सहारे पीपीपी मॉडल को रामबाण इलाज मान रही है। आखिर, निजी क्षेत्र ऐसा क्या करेगा कि बच्चे पढ़ने के लिए अभिप्रेरित हो जाएं, शिक्षक आएं और पढ़ाएं। यह तो एक ही दशा में संभव है ''भय बिन होए न प्रीति'। अब बस एक व्यवस्था बाकी है कि विद्यालयों में भी ''एचआर' की नियुक्ति हो जो ''एम्प्लायी ऑफद मंथ' को चुने। ''इन्सेंटिव' और ''फायर' आदि के लिए आवश्यक निगरानी करे। इसके विपरीत शिक्षा का अधिकार कानून विद्यालय प्रबंधन का एक लोकतांत्रिक मॉडल सुझाता है- ''विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा विद्यालय का प्रबंधन'। दिल्ली के सरकारी विद्यालयों के प्रबंधन में इस मॉडल की सफलता आजकल सुर्खियां बटोर रही है। इसी तरह राजनीतिक इच्छाशक्ति और नीतियों के सुव्यवस्थित निष्पादन का एक अन्य उदाहरण रवाण्डा जैसे छोटे अफ्रीकी देश से आता है, जहां सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता के कारण निजी विद्यालय बंद होने के कगार पर आ चुके हैं। अपने यहां भी कुछ पहल हुई हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि अपने पाल्यों का प्रवेश ''पड़ोस के सरकारी विद्यालय' में कराएं। ''असफल विद्यालय' के तर्क से सरकार दायित्व से पीछा छुड़ा रही है। विद्यालयों की स्वायत्तता के झुनझुने को निजी हाथों में सौंपने से पहले अपनी विरासत को याद कीजिए जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक आत्मनिर्भर और स्वायत्त विद्यालय की परिकल्पना करते हैं, जिसका प्रबंधन स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है और जो पाठ्यर्चया और शिक्षण पद्धति के स्थानीयकरण द्वारा हाथ, हृदय और मस्तिष्क के संयोजन पर बल देता है-''वैज्ञानिक ज्ञान' से समझौता किए बिना।

महिला आरक्षण का सवाल

आभा स्वामी

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते हुए सियासी चाल चली है। कोशिश प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को महिला सशक्तीकरण के मुद्दे पर कठघरे में खड़ा करने की है। इसके बावजूद एनडीए सरकार को ये चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। अगर सरकार संसद और विधानमंडलों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान कर पाई, तो उसकी अनेक सफलताओं के बीच यह एक और अनुपम उपलब्धि होगी। महिला आरक्षण विधेयक की विडंबना यह है कि इसके पक्ष में लगभग पूर्ण राजनीतिक सहमति के बावजूद यह बिल 21 साल से लटका है। इस दौरान केंद्र में विभिन्न प्रमुख दलों की सरकार बनी। मगर किसी ने इसे पारित कराने में वास्तविक रुचि नहीं दिखाई। इस बीच सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस ने दस साल (2004-14) तक केंद्र में सरकार का नेतृत्व किया। उसने 2010 में राज्यसभा से महिला आरक्षण के लिए संविधान में 108वें संशोधन का विधेयक पास जरूर कराया, मगर लोकसभा में आते-आते उसका संकल्प जवाब दे गया। अब सोनिया ने उस समय उस सदन में उनकी पार्टी का अपना बहुमत न होने की आड़ ली है। और प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया है कि वे लोकसभा में अपनी पार्टी के बहुमत का लाभ उठाते हुए ये बिल पारित कराएं। इसके बाद उन्होंने महिला उत्थान के प्रति कांग्रेस की निष्ठा का बखान यह कहते हुए किया कि उनकी पार्टी ने संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के जरिए पंचायतों व नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान किया था। कांग्रेस अध्यक्ष से यह जरूर पूछा जा सकता है कि 2010 में उनकी पार्टी की सरकार ने जो इरादा राज्यसभा में दिखाया, वह लोकसभा में आकर क्यों कमजोर पड़ गया? तब भले कांग्रेस का अपना बहुमत नहीं था, किंतु भाजपा व वाम दलों सहित कई दूसरी पार्टियों का समर्थन बिल के साथ था। बहरहाल, इस मुद्दे पर आरोप-प्रत्यारोप की आवश्यकता नहीं है।

इस साल के आरंभ में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा था कि बिना कोई विवाद किए इस बिल को सम्मानजनक तरीके से पास किया जाना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्षी दल अगर स्पीकर की भावना के मुताबिक आचरण करें, तो विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का उद्देश्य अवश्य पूरा हो सकता है। गौरतलब है कि मौजूदा 543 सदस्यीय लोकसभा में सिर्फ 62 महिला सदस्य हैं। और ये सदस्य संख्या अब तक की उच्चतम है। औसतन भारत में स्त्रियों का सियासी प्रतिनिधित्व दस प्रतिशत के आसपास रहा है।

इस सूरत को बदलना भारत को विकसित एवं आधुनिक देश बनाने के लिए जरूरी है। मोदी सरकार ने जैसे जीएसटी लागू कर परोक्ष कर-व्यवस्था को आमूल रूप से बदल डाला, वैसा ही संकल्प उसे महिला आरक्षण के मामले में दिखाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कठिन निर्णय लेने की अपनी क्षमता से देश को प्रभावित किया है। इसलिए महिलाओं या कहें कि तमाम प्रगतिशील भारतीयों की उनसे ऊंची उम्मीदें हैं। अतः इस मुद्दे पर बीते 21 वर्षों से जारी सियासी खेल पर अब विराम लगना चाहिए।

फर्स्ट लुक के बाद दीपिका की यूनीब्रो वाली 'नई तस्वीरें' सोशल मीडिया पर हो रहीं वायरल

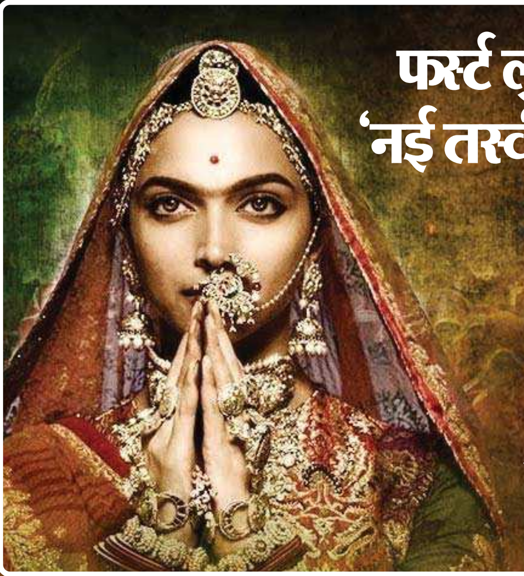

पद्मावती के गेटअप में दीपिका की ये तस्वीरें एक ज्वैलरी एड कैंपेन का हिस्सा हैं। एड कैंपेन शुरू होने से पहले ही तस्वीरें लीक हो चुकी हैं। बता दें, कि पद्मावती के लिए संजय लीला भंसाली ने ज्वैलरी ब्रैंड के साथ टाइअप किया था। इस फोटो में भी दीपिका भारी-भरकम गहनों से लदी दिख रही हैं।

एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म 'पद्मावती' का फर्स्ट लुक पोस्टर और फिल्म में दीपिका का लुक नवरात्र के पहले दिन जारी कर दिया गया है। पोस्टर में दीपिका काफी रॉयल अंदाज में नजर आ रही हैं। गौरतलब है कि फिल्म में दीपिका का किरदार रानी पद्मिनी का है। इसी लुक के साथ दीपिका की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। जिसमें वो एक बार फिर महारानी पद्मावती के शाही लुक में नजर आ रही हैं। वह नथ, गले में हार और मांग-टीका पहने हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पद्मावती के गेटअप में दीपिका की ये तस्वीरें एक ज्वैलरी एड कैंपेन का हिस्सा हैं। एड कैंपेन शुरू होने से पहले ही तस्वीरें लीक हो चुकी हैं। बता दें, कि पद्मावती के लिए संजय लीला भंसाली ने ज्वैलरी ब्रैंड के साथ टाइअप किया था। इस फोटो में भी दीपिका भारी-भरकम गहनों से लदी दिख रही हैं। दीपिका पादुकोण फैन क्लब पर उनकी ऐसी ही कई तस्वीरें शेयर हो रही हैं। 'बॉलीवुड लाइफ' के मुताबिक तस्वीरें पद्मावती के सेट से लीक हुई हैं।

ये फोटोज वायरल हैं। जहां एक उनके फैंस इस लुक को देख उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे वहीं फिल्मी इंडस्ट्री में भी हस्तियां दीपिका के इस लुक की दीवानी हो गई हैं। लेकिन इस लुक में जिस चीज ने सभी का ध्यान सबसे ज्यादा अपनी ओर केन्द्रित किया, वह है दीपिका की जुड़ी हुई आईब्रो (भौंहें)। इसे लेकर लोगों में ऐसा रखने की वजह जानने की जिज्ञासा बढ़ गई है। इस फिल्म में दीपिका के लुक को खासतौर पर राजपूताना महारानी से मिलता-जुलता दिखाया गया है। यही वजह है कि उनके इस लुक की तुलना राजपूताना रानियों की पुरानी पेंटिंग्स से भी हो रही है। बताया जाता है कि रानी पद्मावती की अधिकतर पेंटिंग्स में वह भी यूनीब्रो के साथ ही नजर आई हैं। बता दें कि इस फिल्म के लिए तैयार होने में दीपिका पादुकोण को सिर्फ आधा घंटा ही लगता था। यही कारण था कि दीपिका को उस समय का लुक देने के लिए जुड़ी हुई भौहों का इस्तेमाल किया गया है। गौरतलब है कि फिल्म में दीपिका के अलावा रणवीर सिंह और शाहिद कपूर भी मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं।

भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान कपिल देव का किरदार निभायेंगे रणवीर सिंह

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह सिल्वर स्क्रीन पर कपिल देव का किरदार निभाते नजर आ सकते हैं। बॉलीवुड में इन दिनों बायोपिक और खेल पर आधारित फिल्मों का चलन जोरो पर है। 'मैरी कॉम', 'मिल्खा सिंह', 'एमएस धोनी' एवं 'मोहम्मद अजहरूद्दीन' के बाद अब इस फेहरिस्त में कपिल देव का नाम सामने आया है। निर्देशक कबीर खान भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव की जिंदगी पर फिल्म बनाने वाले हैं। चर्चा हो रही है कि फिल्म में कपिल देव का रोल रणवीर सिंह निभाएंगे। पहले चर्चा थी कि इसके लिए अजरुन कपूर को अप्रोच किया गया है। लेकिन इस रोल के लिए शायद रणवीर सिंह बाजी मार ली है। रणवीर सिंह पहली बार किसी बायोपिक में काम करेंगे। 'बाजीराव मस्तानी' और 'पद्मावती' जैसी पीरियड फिल्मों के बाद रणवीर को एक क्रिकेटर के तौर पर रुपहले पर्दे पर देखना काफी दिलचस्प होगा। बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते रणवीर सिंह और कबीर खान की मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच कई घंटे तक बातचीत हुई।

कबीर खान की निर्देशित इस फिल्म को फैंटम फिल्म प्रोड्यूस करेगी, हालांकि रणवीर ने अभी सहमति नहीं दी है लेकिन 'बजरंगी भाईजान' और 'एक था टाइगर' जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में बनाने वाले निर्देशक के साथ रणवीर सिंह काम जरूर करना चाहेंगे। आज एक कार्यक्रम में कबीर खान ने बताया कि वो इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरु करने वाले है। कपिल देव भारतीय क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, कपिल देव की अगुवाई में ही भारतीय टीम ने 1983 का विश्वकप जीता था, कपिल देव भारत के सबसे सफल कप्तानो में से एक रहे है।

तब्बू ने स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही साइन की रोहित शेट्टी की फिल्म 'गोलमाल अगेन'

तब्बू ने रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी गोलमाल सीरीज की चौथी फिल्म 'गोलमाल अगेन' में काम किया है। फिल्म में अजय देवगन, परिणीति चोपड़ा श्रेयस तलपड़े, कुणाल खेमू, अरशद वारसी, तुषार कपूर और जॉनी लीवर की भी अहम भूमिकाएं हैं। साथ ही करीना कपूर को रिप्लेस कर परिणीती चोपड़ा की फिल्म में एंट्री होने जा रही हैं।

रोहित शेट्टी की फिल्म 'गोलमाल अगेन' दिवाली पर रिलीज होने को तैयार है। वहीं, अभिनेत्री तब्बू का कहना है कि उन्होंने कई सितारों से सजी इस फिल्म को पटकथा पढ़े बिना ही साइन कर लिया था। तब्बू ने रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी गोलमाल सीरीज की चौथी फिल्म 'गोलमाल अगेन' में काम किया है। फिल्म में अजय देवगन, परिणीति चोपड़ा श्रेयस तलपड़े, कुणाल खेमू, अरशद वारसी, तुषार कपूर और जॉनी लीवर की भी अहम भूमिकाएं हैं। साथ ही करीना कपूर को रिप्लेस कर परिणीती चोपड़ा की फिल्म में एंट्री होने जा रही हैं। परिणीती ने बताया जब फिल्म का पहला पार्ट रिलीज़ हो रहा था तब वो अपने स्कूल के एग्जाम दे रही थी। जब मैं न्यूयॉर्क में थी तब मुझे रोहित सर ने कॉल किया था। तब मुझे विश्वास ही नहीं हो पाया की अब मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। फिल्म के ट्रेलर लांच के दौरान तब्बू ने शुक्रवार को मीडिया को बताया कि वह हमेशा से इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहती थीं। तब्बू ने बताया कि वह हमेशा से इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहती थीं। तब्बू ने कहा, यह मेरे लिए खास फिल्म है, क्योंकि जब भी मैंने 'गोलमाल' श्रृंखला की फिल्म देखी, मैं लगातार हंसते-हंसते लोटपोट हो जाती थी। जब भी पार्टियों में रोहित से मिलती तो कहती कि मैं इस श्रृंखला का हिस्सा बनना चाहती हूं। यहां तक कि मैं मेहमान भूमिका करने के लिए भी तैयार थी। मैं कहना चाहूंगी कि यह उन फिल्मों में से एक है, जिसकी पटकथा शूटिंग से पहले मैंने नहीं सुनी, क्योंकि मैं जानती थी कि उनके पास मेरे लिए कुछ अच्छा है। यह एक तरह से पिकनिक जैसा था। बता दें 'गोलमाल अगेन' दिवाली के मौके पर यानी की 19 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली है।

उम्र के मुताबिक किरदार निभाना चाहते हैं संजय दत्त

बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त अब उम्र के मुताबिक किरदार निभाना चाहते हैं। संजय दत्त की कमबैक फिल्म 'भूमि' रिलीज हो चुकी है। जहां अधिकतर अभिनेता बड़े पर्दे पर अपनी वास्तविक उम्र से कम उम्र के किरदार निभा रहे हैं वहीं संजय दत्त का कहना है कि वह बडे पर्दे पर अपनी उम्र के मुताबिक ही किरदार करना चाहते हैं। संजय दत्त ने फिल्म में अदिति राव हैदरी के पिता की भूमिका निभायी है। संजय दत्त अभी करीब आठ से नौ फिल्मों पर काम कर रहे हैं जिनमें मुन्नाभाई सीरिज की एक फिल्म के अलावा 'साहेब बीवी और गैंगस्टर 3', 'मलंग', 'शिद्दत', 'माकरे भाऊ', 'तोरबाज' और निशिकांत कामथ की एक फिल्म शामिल है। संजय दत्त ने कहा, मैं अपनी उम्र के मुताबिक पटकथाओं पर काम कर रहा हूं जो कि मैं करना चाहता हूं ,मुझे लगता है कि यह एक ऐसी शैली है जिसपर भारत में काम नहीं किया जाता। मैं वह करना चाहता हूं। जब मैं जेल में था उस दौरान मेरे सोचने के तरीके में काफी बदलाव आया। मैंने अपनी दाढ़ी को सफेद होते देखा है। अब में पेड़ के ईद गिर्द या कॉलेज परिसर में नाच नहीं सकता। मैं अपनी उम्र के मुताबिक किरदार करना चाहता हूं। बता दें की संजय दत्त के फिल्म 'भूमी' में संजय दत्त एक पिता का किरदार निभाते हुए नजर आये है। इस फिल्म में संजय दत्त के अलावा अदिति राव हैदरी, शरद केलकर भूमिका में है।

संजय दत्त ने फिल्म में अदिति राव हैदरी के पिता की भूमिका निभायी है। संजय दत्त अभी करीब आठ से नौ फिल्मों पर काम कर रहे हैं जिनमें मुन्नाभाई सीरिज की एक फिल्म के अलावा 'साहेब बीवी और गैंगस्टर 3', 'मलंग', 'शिद्दत', 'माकरे भाऊ', 'तोरबाज' और निशिकांत कामथ की एक फिल्म शामिल है। संजय दत्त ने कहा, मैं अपनी उम्र के मुताबिक पटकथाओं पर काम कर रहा हूं जो कि मैं करना चाहता हूं ,मुझे लगता है कि यह एक ऐसी शैली है जिसपर भारत में काम नहीं किया जाता।

सनी लियोन के विवादित विज्ञापन से बढ़ी कॉन्डम की बिक्री

हिंदू संगठनों और व्यापार निकायों के विरोध के बाद कॉन्डम की सेल 35 फीसदी बढ़ी

अहमदाबाद । गुजरात में नवरात्र के दिनों में एक कॉन्डम कंपनी के विज्ञापन पर हिंदू संगठनों और व्यापार निकायों ने विरोध जताया था। इसके बाद सड़कों से इसके होर्डिंग्स भी हटा दिए गए थे लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी के बाद कॉन्डम की सेल 35 फीसदी तक बढ़ गई है और कंपनियों को खूब फायदा हो रहा है। दरअसल बीते दिनों गुजरात की सड़कों पर कॉन्डम के विज्ञापन पर इसकी ब्रांड अंबेस्डर सनी लियोन की तस्वीर के साथ होर्डिंग लगाई गई थी जिसके पोस्टर में गुजराती भाषा में टैगलाइन लिखी थी, आ नवरात्री ए रामो, परानतु प्रेमथी जिसका हिंदी में अर्थ था नवरात्र में खेलें...मगर प्यार से। विरोध कर रहे तमाम हिंदू संगठनों का कहना था कि ये विज्ञापन हिंदू भावनाओं को ठेस

पहुंचाने जैसा है। वहीं बात करें मार्केट की तो नवरात्र के दिनों में कॉन्डम के साथ-साथ गर्भनिरोधक की मांग में हमेशा इजाफा रहता है और इनकी बिक्री भी अच्छी होती है। इस साल भी यह दर 35 फीसदी तक बढ़ गई है।

गुजरात स्टेट फेडरेशन के केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोशिएसन (जीएसएफसीडीए) के चेयरमैन जशवंत पटेल कहते हैं कि नवरात्र के दौरान कॉन्डम और गर्भनिरोधक की मांग हमेशा बढ़ जाती है। इस बार ये मांग त्योहार से पहले ही है और बिक्री भी अच्छी है। पटेल बताते हैं कि इस दौरान कई पान दुकानों ने भी देर रात तक दुकान खोलकर कॉन्डम बेचना शुरू कर देते हैं। कंपनी के एक अनुमान के अनुसार कॉन्डम और गर्भनिरोधक का मासिक कारोबार दो करोड़ से ऊपर रहता है जो नवरात्र के दिनों में 30 से 35 फीसदी तक बढ़ जाता है। इस वजह से हर ब्रांड खासकर इस त्योहार में अपने प्रचार के प्रयास में जुटे रहते हैं। आरएसएस से जुड़ी डॉक्टरों की संस्था गुजरात नेशनल मेडिको ऑर्गनाइजेशन (जीएनएमओ) ने अपने 7000 सदस्यों को फार्मा द्वारा निर्मित किसी भी दवा की सलाह देने से मना किया है। जीएनएमओ ने अध्यक्ष डॉ. प्रकाश कुर्मी ने कहा है कि कंपनी ने जो विज्ञापन में कंटेट का इस्तेमाल किया है उससे हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंची हैं। सोशल मीडिया पर इस विज्ञापन को हटाने और माफी की मांग करते हुए कंपनी के खिलाफ एक कैंपेन शुरू किया है। वहीं कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि नवरात्र होर्डिंग कैंपेन का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था और जल्द ही इसे हटा भी दिया गया है।

रेडियन्ट स्कूल में फीस को लेकर अभिभावक हल्ला बोल, पुलिस को बुलानी पड़ी

सूरत दर्पण संवाददाता

सूरत। इस घटना में अभिभावकों ने यह भी बताया कि स्कूल की फीस के मुद्दे पर बच्चों को प्रताड़ित भी किया जा रहा था। शहर की अनेक स्कूलों में फिलहाल फीस को लेकर विवाद चल रहा है। इसके बावजूद अभिभावक बच्चों के भविश्य को ध्यान में रखकर फीस भर ही रहे हैं, ऐसे में पिपलोद की रेडीयेन्ट इंग्लिश ऐकेडमी स्कूल में दुसरे सत्र की फीस नहीं भरने वाले विद्यार्थियों को प्रताड़ित करने से वे मानसिक तनाव का अनुभव कर रहे है। जिसे लेकर आज 200 से 250 अभिभावक एकत्रित हुए और उसके बाद स्कूल संचालकों को फीस के मामले में आक्रोषित पेशकश करने के लिए पहुँचे। हालांकि स्कूल के संचालकों ने कहा कि पहले फीस भरो बाद में तुत्हें सुनेंगे और मार्कशीट देंगे। ऐसा कहने पर बात बिगड़ गई।

अभीभावकों ने बताया कि स्कूल संचालकों की ऐ तानाशाही के खिल अभिभावकों ने आखिर मे हाथ में लिया और स्कूल परि में हल्ला मचाकर अपना गु व्यक्त किया। पहले सत्र की फ भरी होने के बाद भी कक्षा 1 3 के विद्यार्थियों के परिण अटका दिये गए। जिसके प स्कूल संचालकों ने विद्यार्थियों वश में करने का प्रयास कर होने का आरोप अभिभावको लगाया।

विवाहिता को घर से निकाला, ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज

सूरत दर्पण संवाददाता

सूरत। अलथाणा आर्शिवाद विला में रहने वाली खुशबू का विवाह वर्ष 2011 में वेसू स्थित हेप्पी रेसीडेंसी में रहने वाले अंकित अग्रवाल के साथ हुआ था। शादी के 7 साल बीतने के बाद भी खुशबू को संतान नहीं हो रही थी। जिसके कारण अग्रवाल परिवार के तमाम सदस्य खुशबू को शारीरिक और मानसिक यातनाएं देते थे। पिछले काफी समय से खुशबू को उसके पति और ससुराल वालों ने घर से धक्के मारकर निकाल दिया। यातनाओं से तंग आकर आखिर खुशबू ने न्याय के लिए पुलिस से गुहार लगाई। जिससे पति अंकित अग्रवाल, ससुर कमलकांत अग्रवाल, सास शोभा अग्रवाल ननद आर्ची अग्रवाल और ब्रह्म कुमार हरीचरणलाल गर्ग के खिलाफ उमरा पुलिस ने परिणिता की शिकायत के आधार पर तहकीकात शुरु की है। बताया जा रहा है कि शिकायत होने के बाद अग्रवाल परिवार कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए छूमंतर हो गया है। हालांकि पुलिस ससुराल वालों को ढूंढ रही है।

30.83 लाख की ठगी

सूरत। मोटा वराछा स्थित सिटीलाईट सोसायटी में अतुल देवाणी रहते हैं और उनकी कपड़े की दुकान रिंग रोड स्थित रघुकुल मार्केट में है। नवागांव डिंडोली में रहने वाले पौषक शक्तावत अणुव्रत द्वार के संजय चेवली और कपड़ा दलाल रजनीकांत मिस्त्री तथा गोपाल चौधरी ने मिलकर शुरुआत में व्यापारी के पास साड़िया लेकर जॉबवर्क करवाकर समय पर पेमेन्ट दिया। लेकिन 20 मार्च से 15 जून के दौरान व्यापारी के पास से डाईड साड़ी 5908 नग, लेकर मजदूरी के रुपये 30.83 लाख रुपये नहीं चुकाकर ठगी कर कपड़ा व्यापारी को धोका देकर दलाल समेत तीनों व्यापारी गायब हो गए। आखिरकार अतुल की शिकायत के आधार पर सलाबतपुरा पुलिस ने फरार कपड़ा व्यापारियों को ढूंढने की कार्यवाही शुरु की है।

स्वाईन फ्लू एक रिपोर्ट पॉजेटिव

सूरत। दो दिनों के दौरान कोई मरीज दर्ज नहीं होने के बाद आज एक और मरीज की रिपोर्ट पॉजेटिव आने के बाद स्वाईन में मरीजों की संत्या 367 है। अभी भी स्वाईन त्त्लू के 5 मरीज ईलाज के लिए अलग-अलग अस्पताल में भर्ती हैं। जिनमें 1 मरीजों की हालत सामान्य है, 2 मरीजों का ऑत्सीजन सपोर्ट पर ईलाज चल रहा है। एक मरीज को वेन्टलेटर पर और बीपेप पर 1 मरीज को रखा गया है। 2 मरीजों का ईलाज पूर्ण होने के कारण उन्हें डिस्चार्ज किया गया। जिसका रिपोर्ट पोजेटिव आया है वह केवल 9 महिने का बच्चा है जो सायण रोड, अमरोली में रहता है।

पांडेसरा 39.38 लाख का चूना

सूरत। पांडेसरा चीकूवाड़ी में रहने वाले गिरधर बीरगांव की हरीओम मार्केट में कपड़े की दुकान है। मूल राजस्थान निवासी और हरीओम मार्केट की दुकान के मालिक नेमाराम चौधरी तथा हीराबाग में रहने वाले कपड़ा दलाल अमृत वाडोदरिया ने 22 से 26 अप्रैल के दौरान व्यापारी विरमगांम के पास से अलग-अलग बिल और चालान के माध्यम से 48 लाख रुपये कीमत का लेस पट्टी का माल खरीदा, लेकिन रुपये चुकाने के बजाय दुकान बंद कर फरार हो गया। काफी ढूंढने के बाद भी व्यापारी और दलाल का पता न चला तो पीड़ित व्यापारी ने दलाल और व्यापारी के खिलाफ सलाबतपुरा पुलिस थाने मे शिकायत दर्ज करवाई। जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है।

रांदेर में लाखों की चोरी

सूरत। रांदेर रामनगर गोवर्नमेन्ट त्वाटर्स के पीछे भाग्यलक्ष्मी सोसायटी में रहने वाले 58 वर्षीय धनजी गोहिल की अडाजन हनीपार्क रोड

सूरत। तू खींच मेरी फोटो', 'गोरी टॉ लागे', 'आंखलडी राती रे उजागरो त्या कर्यो' पवित्र शारदीय नवरात्रि के दूसरे दि युवाओं ने गरबा ग्राउंड में धूम मचा दी। शह से बारिश के माहौल के गायब होते ह युवाओं में एक नया उत्साह और जो दिखाई दे रहा है। लोगों ने मन-भरकर गर कर मां की आराधना की। शहर क अधिकांश सोसायटियों में गली गरबे की धू है। नवरात्रि में युवाओं ने झूमकर गरब खेला। इसके साथ ही वराछा इलाके आयोजित पाटीदार गरबा में भी युवाओं जय सरदार के नारे के साथ गरबा खेला

गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष भरतसिंह सोलंकी की माता का निधन

अहमदाबाद । गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भरतसिंह सोलंकी की माता विमलाबेन सोलंकी का आज निधन हो गया। गुजरात के पूर्व मुत्त्यमंत्री माधवसिंह सोलंकी की पत्नी विमलाबेन सोलंकी पिछले काफी समय से बीमार थीं। विमलाबेन का गांधीनगर के सिविल अस्पताल के आईसीयू वार्ड में उपचार चल रहा था। जहां आज दोपहर उनका निधन हो गया। 24 सितंबर को सुबह 10 बजे उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। विमलाबेन के निधन की खबर मिलते ही बड़ी संत्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता गांधीनगर स्थित भरतसिंह सोलंकी के निवास पर पहुंच गए और उनकी माता के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें सांत्वना दी। भाजपा नेताओं ने भी सोलंकी की माता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

आदिवासी बंधुओं को उनके अधिकार दिलाएगा जनविकल्प मोर्चा : वाघेला

अहमदाबाद । गुजरात के पूर्व मुत्त्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला ने आज कहा कि जन विकल्प मोर्चा आदिवासी बंधुओं को उनके अधिकार दिलाएगा। कांग्रेस छोड़ हाल ही में जन विकल्प मोर्चा में शामिल हुए शंकरसिंह वाघेला ने आज फागवेल में भाथीजी महाराज के दर्शन करने के बाद दूसरे दिन की चुनाव प्रचार यात्रा का प्रारंभ किया। फागवेल में बड़ी संत्या में उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए वाघेला ने सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्ष कांग्रेस पर कड़े प्रहार किए। फागवेल से निकलकर वाघेला डाकोर पहुंचे, जहां रणछोड़रायजी और बाद में हालोल के पावागढ़ स्थित महाकाली माता के दर्शन किए। पावागढ़ में वाघेला ने स्थानीय लोगों से बातचीत की ओर उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर उनके साथ चर्चा भी की। पावागढ़ से बोडेली पहुंचे शंकरसिंह का आदिवासी बंधुओंने परंपरागत नृत्य और फूलहार से उनका भव्य स्वागत किया। बोडेली में आयोजित वाघेला के रोड शो में बड़ी संत्या में लोग शामिल हुए।

वाघेला ने कहा कि सरकार आदिवासियों के अधिकार छीनकर उनके साथ अन्याय कर रही है। भाजपा और कांग्रेस केवल वादे करने में माहिर हैं और दोनों ही पार्टी हमेशा आदिवासी समाज की समस्या का समाधान करने में निष्फल रही हैं। ऐसे हालात में तीसरे विकल्प यानि जनविकल्प मोर्चा को भारी मतों से विजयी बनाना जरूरी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनविकल्प मोर्चा के सच्चे जनप्रतिनिधि होंगे।

वापी में तीन साल की बच्ची से 4 लोगों ने किया रेप

दमण के अस्पतालों ने नहीं किया इलाज

वापी। वापी में चार लोगों ने तीन साल की बच्ची साथ दुष्कर्म कर पानी से भरी बाल्टी में डुबोकर मार का प्रयास किया। गंभीर हालत में परिजन बच्ची क वलसाड हॉस्पिटल ले गए, जहां से उसे सूरत सिवि अस्पताल रेफर किया गया। डॉत्टरों के अनुसार बच्च की हालत गंभीर है। वापी चाल निवासी बच्ची के पि ने वलसाड सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस उन्होंने कहा है कि गुरुवार को वे पड़ोस में क्रिके मैच देख रहे थे। इसी दौरान उनकी बड़ी बेटी ने छो बहन के घर से गायब होने की बात कही। बच्ची क तत्काल खोजा जाने लगा तो एक पड़ोसी ने बताया वह मकान के आखिरी कमरे में सो रही है। जब पीड़ि बच्ची के परिजन कमरे में पहुंचे तो वहां 22-23 सा के चार युवक बैठे थे। बच्ची के पिता को देखते ही वे भाग निकले। बच्ची पानी से भरी बाल्टी पाई गई। उसका सिर नीचे था। मुंह में कपड़े ठुंसे थे और प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। आनन फानन में बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे सूरत रेफर कर दिया। बच्ची के पिता आरोप लगाया कि गंभीर हालत में बेटी को दमण के दो अस्पतालों में ले गए, लेकिन डॉत्टरों ने र केस कहकर इलाज से इनकार कर दिया। उन्होंने डॉत्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग क वापी के डीवाईएसपी एचएम कुंडलिया ने कहा कि बच्ची की मां ने चार लोगों पर रेप का आर लगाया है। सभी का लोकेशन मिल गया है। वलसाड एसओजी व एलसीबी की टीम आरोपियों व

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा 4 ओ-ब्लाक आगम नवकार कॉम्पलेक्ष सचीन रेल्वे स्टेश के पास,सूरत, जि. सूरत, गुजरात से प्रकाशित, एवं तापीलोक पब्लिकेशन 152,153 श्री राम इंडस्ट्रीयल एरिया पांडेसरा सूरत 394210 से मुद्रत, फोन नं. 9879141480 संपादक सुरेश मौर्या (पी आर बी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी) E-mail: krantisamay@gmail.com